## जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड

## बनाम

## चांद्रमल जैन और अन्य

## 7 फरवरी, 1966

(पी.बी.गजेन्द्रगडकर, सी.जे., के.एन.वांचू, एम.हिदायतुल्ला,

वी.रामास्वामी और पी. सत्यनारायणा राजू, जे.जे.)

बीमा-स्वीकृति और कवर नोट बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए -पॉलिसी जारी नहीं की गई-पॉलिसी की शर्तें क्या अनुबंध पर लागू होती हैं -पक्षकारान् को अनुबंध रद्द करने की अनुमति देने वाली शर्त उचित है -वैध होने पर बीमाकर्ता द्वारा रद्दीकरण।

प्रस्तावों की स्वीकृति के पत्र और कवर नोट अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा जारी किए गए थे, जिसका उद्देश्य आग, बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान के खिलाफ उत्तरदाताओं के कुछ घरों का बीमा करना था। कवरनोट के अनुसार बीमा "सोसायटी की नीतियों की सामान्य शर्तीं के अधीन था। हालाँकि, सोसायटी ने उस समय तक नीतियां जारी नहीं की थीं, जब गंगा, जिसके किनारे पर घर थे, में बाढ़ आने लगी थी। इसके तुरंत बाद सोसायटी ने अपनी अग्नि पॉलिसी की शर्त (10) पर भरोसा करते हुए जोखिम को रद्द कर दिया। घर बह गए और उत्तरदाताओं ने

नीतियों के तहत भुगतान की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। ट्रायल जज ने इसे खारिज कर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। निर्धारण के लिए प्रश्न थे, कि क्या अग्नि पॉलिसी की शर्त (10) मामले के तथ्यों पर लागू थी, क्या उक्त शर्त उचित थी और क्या सोसायटी द्वारा पॉलिसी को रद्द करना वैध था:

अभीनिर्धारितः (1) प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र और कवर नोट्स को देखने से यह स्पष्ट था कि आग और बाढ, चक्रवात आदि को कवर करने के लिए विस्तारित मानक पॉलिसी के तहत बीमा का एक अनुबंध अस्तित्व में आ गया था। तथ्य यह है कि पॉलिसी वास्तव में वितरित नहीं की गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब बीमा का अनुबंध पूरा हो जाता है तो यह मायने नहीं रखता है कि नुकसान के बाद पॉलिसी वास्तव में वितरित की गई है या नहीं और इसी कारण से पक्षकारान के अधिकार पॉलिसी की स्वीकृति और वितरण के बीच पॉलिसी द्वारा नियंत्रित होते हैं। भले ही कोई शर्तें निर्दिष्ट न हों, ऐसे मामले में प्रथागत रूप से जारी की गई पॉलिसी में निहित शर्तें लागू होती हैं। वर्तमान मामले में उन्होंने कवर नोट्स में स्पष्ट रूप से कहा कि सोसायटी की नीतियों की सामान्य शर्तें लागू होंगी। शर्त (10) ऐसी नीतियों की एक सामान्य शर्त थी और इसलिए इसे समाज द्वारा लागू किया जा सकता था। (510 बी, 512 डी-जी)

- (2) बीमा अनुबंध में अनुबंध रद्द करने की पारस्परिक शर्त शामिल करने में कुछ भी गलत नहीं है। अग्नि पॉलिसी की शर्त (10) दोनों पक्षों को रद्दीकरण का समान अधिकार देती थी और अनुचित नहीं थी। (513 बी सी)
- (3) शर्त (10) जैसी शर्त का उद्देश्य जोखिम को रद्द करना है लेकिन जो नुकसान हुआ है उसके लिए दायित्व से बचना नहीं है या जोखिम से बचना है जब यह पहले से ही नुकसान में बदल रहा हो। पॉलिसी के तहत दायित्व शुरू होने या अपरिहार्य होने से पहले रद्दीकरण उचित रूप से संभव है और प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि रद्दीकरण वैध है या अवैध। मामले के तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि नुकसान शुरू होने या अपरिहार्य हो जाने के बाद सोसायटी ने पॉलिसियां रद्द कर दीं। इसलिए रद्दीकरण वैध था। (514 एच-515 सी, 515 जी)

सन फायर कार्यालय बनाम हार्ट वगैरह (1889) 14 ए.सी. 98 ए डी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम हार्टफॉर्ड फायर इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड एन.आई.आर. (1956) एस.सी. 1288 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्रः सिविल अपील नं. 886/1963

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपील सं. 44/1959 में निर्णय व डिक्री दिनांकित 13/14 जुलाई, 1961 के विरूद्ध अपील सी.बी.अग्रवाल, बी.एम.अग्रवाल और आई.एन.श्रॉफ, अपीलार्थी की ओर से

निरेन डी, अतिरिक्त महाअधिवक्ता, जी. एल. सांगी, निर्मल कुमार घोसल, जे.बी.दादाचंजी, ओ.सी. माथुर और रविन्द्र नारायण, प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया द्वारा

हिदायत्ल्लाह जे. यह अपील कलकता उच्च न्यायालय 13 और 14 जुलाई, 1961 के निर्णय से ली गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच ने अपने ही न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए, प्रतिवादियों के हर्जाने के दावे पर फैसला सुनाया। परिस्थितियां यह थी। अपीलकर्ता एक सामान्य बीमा कंपनी है। 2 जून 1950 को उत्तरदाताओं ने धुलियान में होल्डिंग नंबर 274, 274/ए.बी.सी और डी और 273, 273/ए.बी.सी और डी वाले कुछ घरों को आग से बचाने और चक्रवात, बाढ़ और/या नदी के मार्ग में परिवर्तन या नदी के कटाव, भूस्खलन और धंसाव से ह्ए नुकसान या क्षति सहित क्रमशः 51,000/- रुपये और 65,000/- रुपये का बीमा करने की दृष्टि से कंपनी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। धुलियान शहर गंगा के तट पर स्थित है और कई वर्षों से नदी अपना रास्ता बदल रही थी और 1949 में शहर का एक हिस्सा बह गया था। बीमा स्पष्ट रूप से इस जोखिम को ध्यान में रखकर

किया गया था। बीमा की अवधि 3 जून 1950 से 2 जून 1951 तक होनी थी। कंपनी ने 3 जून 1950 को दो पत्रों (प्रदर्श-डी) द्वारा प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और पत्रों में कहा गया कि प्रस्ताव के अनुसार दिया गया आश्वासन कवर नोटस संलग्न पत्रों के तहत कवर्ड था। इन स्वीकृति पत्रों के पीछे, घरों का विवरण और एक पृष्ठांकन था जिसमें लिखा था:

"इसमें चक्रवात, बाढ़ और/या नदी के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन और/या नदी के कटाव,भूस्खलन और/या धंसाव से होने वाली हानि शामिल है। यह भी आगे उल्लेखित है कि उपरोक्त परिसर के 50 फीट के भीतर निवास की एक फूस की इमारत है।"

दो प्रस्तावों के संबंध में दो अंतरिम सुरक्षा कवर नोट संख्या 118848 और 18850 बीमा कंपनी द्वारा लिखित बयान के साथ दायर किए गए थे और कहा गया था कि वे स्वीकृति पत्र के साथ भेजे गए कवर नोट्स की प्रतियां थीं, लेकिन उन पर 05, जून 1950 की तारीख अंकित थी। इस बात पर कुछ विवाद है कि क्या वे प्रस्तावों की स्वीकृति दर्शाने वाले उत्तर के साथ संलग्न थे। दो कवर नोट्स में जो समान हैं, विवरण के अलावा हम केवल एक ही पढ़ सकते हैं।

"मैसर्स चंदमुल लाल चंद, पी.ओ. धुलियान मुर्शिदाबाद निम्नलिखित संपत्ति पर 51,000/- रुपये के लिए आग से होने वाले नुकसान का बीमा कराने के इच्छुक हैं,

एक पक्का निर्मित एवं छतयुक्त भवन (सी.जे. विज्ञांडा) होल्डिंग नंबर 274, 274 ए, 274 बी और 274 सी निवास के लिए उपयोग हेतु लिया गया है और/या हाइड्रोजनीकृत जी नट तेल (वनस्पति) और सुरक्षा माचिस के भंडारण के लिए दुकान, धुलियान, वार्ड नं. चार, जिला मुर्शिदाबाद में भी स्थित है।

'इसमें चक्रवात, बाढ़ और/या नदी के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन और/या नदी के कटाव, भूस्खलन और/या धंसाव से होने वाली हानि या क्षिति शामिल है।

यह भी आगे उल्लेखित है कि उपरोक्त परिसर के 50 फीट के भीतर निवास की एक फूस की इमारत है।'

3 जून, 1950 से 3 जून, 1951 तक एक वर्ष के लिये।

आवेदक के प्रस्ताव की शर्तों और सोसायटी की नीतियों की सामान्य शर्तों के अधीन, उक्त संपित को आग से होने वाली क्षिति के विरुद्ध बीमाकृत रखा जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यह सुरक्षा नोट, किसी भी परिस्थिति में तीस दिनों से अधिक लंबी अविध के लिए लागू नहीं हो सकता है, और यह पॉलिसी की डिलीवरी के साथ उस तिथि से पहले तुरंत समाप्त हो जाता है, या यदि जोखिम ऐसी गिरावट की अधिसूचना के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है

प्रीमियम: रू. 892-8-0 आग 28 प्रतिशत की दर पर

प्रीमियमः रू. 892-8-0 बाढ़ और अन्य जोखिम 12 प्रतिशत की दर पर

प्रीमियम: रू. 1,275-0-0."

7 जून को, बीमाकृत ने चेक द्वारा प्रीमियम भेजा।चूंकि उन्हें कोई पॉलिसी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए बीमित व्यक्ति ने 1 जुलाई (प्रदर्श ए/जी) को एक पत्र लिखकर पॉलिसी या कवर नोट्स के विस्तार की मांग की। ऐसा नहीं किया गया।

6 जुलाई, 1950 को कंपनी ने बीमाकृत को दो एक जैसे पत्र (पॉलिसी की राशि और संख्या में परिवर्तन को छोड़कर) लिखे, जिनमें लिखा था,

,	''कलकता	6 जुलाई,	1950

प्रेषिति

मेसर्स चांदमुल लाल चंद,

पी.ओ. धुलियान,

	$\sim$			
म	[5]	ս	ब	द
ຸ ລ	- •	- •		

महोदय,	

इस कंपनी में दर्ज निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, हम 6 जुलाई 1950 से जोखिम को रद्द करते हैं जैसा नीचे उल्लेखित है। संबंधित अनुमोदन की तैयारी चल रही है और उचित समय पर आपको भेज दिया जाएगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)इलिजिबल

एजेन्ट प्रबंधक एवं बीमाकर्ता

परिवर्तन की प्रकृतिः

उपरोक्त कवर नोट जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड द्वारा 6 जुलाई 1950 से रद्द कर दिया गया है।"

15 जुलाई, 1950 को बीमाकृत ने यह कहते हुए लिखा कि उन्होंने कंपनी को बाध्य रखा क्योंकि जब प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और स्वीकार किए गए तो नदी द्वारा कोई कटाव नहीं हुआ था, कंपनी उस समय अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी जब किनारे नदी द्वारा कट रहे थे। उन्होंने इस पत्र को यह कहकर समाप्त किया

"अब जब कटाव और/या नदी के मार्ग में परिवर्तन और/या धंसाव शुरू हो गया है, तो बीमा के किसी अन्य कार्यालय के साथ कोई भी एहतियाती उपाय लेना या इस स्तर पर इसे सुनिश्चित करना काफी असंभव है।"

17 जुलाई, 1950 को कंपनी ने जोखिम को रद्द करने वाली पॉलिसियों के लिए एक पृष्ठांकन तैयार किया और बीमाधारक को पृष्ठांकन भेज दिया। पृष्ठांकन पढ़े:

मेसर्स. चांदमुल लाल चंद, पी.ओ. धुलियान, मुर्शिदाबाद. के नाम पर

यह एतद्द्वारा घोषित और सहमत किया जाता है कि 6 जुलाई 1950 से इस पॉलिसी द्वारा बीमा द जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, कलकता द्वारा रद्द कर दिया गया है, और प्रीमियम का रिफंड रुपये........... बीमाकृत को आनुपातिक आधार पर एतद्द्वारा स्वीकार किया गया।

(हस्ताक्षर)इलिजिबल

एजेन्ट प्रबंधक एवं बीमाकर्ता

कलकता,

77

पत्र के उत्तर में कहा कि चूंकि जोखिम पहले ही "शुरू हो चुकी है" और "घटित हो चुकी है", इसिलए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीमाकृत के पास पुनर्बीमा करके एहितियाती कदम उठाने का समय नहीं बचा है। जवाब में कंपनी ने फायर पॉलिसी की शर्त 10 का हवाला दिया जिसके तहत कंपनी ने किसी भी समय पॉलिसी को रद्द करने का दावा किया। फायर पॉलिसी की शर्त 10 पढ़ें:

"10. यह बीमा बीमाकृत के अनुरोध पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में सोसायटी पॉलिसी लागू होने के समय के लिए प्रथागत लघु अविध दर को बरकरार रखेगी। यह बीमा सोसायटी के विकल्प से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, बीमाकृत को इस आशय का नोटिस दिए जाने पर, जिस स्थिति में सोसायटी रद्दीकरण की तारीख से समाप्त न हुई

शर्तों के लिए प्रीमियम का एक उचित अनुपात मांगने पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी।"

जवाब में बीमाकृत ने 2 अगस्त को लिखा कि यह शर्त आग के अलावा किसी भी जोखिम पर लागू नहीं होती है और किसी भी स्थिति में जोखिम शुरू होने के बाद कंपनी की रक्षा नहीं की जा सकती थी। 13 और 15 अगस्त को घर बह गए। पॉलिसियों के तहत भुगतान की असफल मांग के बाद, बीमाकृत ने वर्तमान मुकदमा कलकता उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में दायर किया। इसे जी.के. मित्तर जे. द्वारा जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील में दावा 1,10,000/- रुपये जुर्माना सिहत की सीमा तक डिक्री कर दिया गया था। डिक्रीटल राशि पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। उच्च न्यायालय ने अपील के लिए मामले को उपयुक्त प्रमाणित किया और वर्तमान अपील कंपनी द्वारा दायर की गई है।

इससे पहले कि हम विवादित प्रश्न पर विचार करें, हम सामान्य तौर पर गंगा नदी की स्थिति धुलियान शहर और विशेष रूप से बीमाकृत घरों के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। धुलियान शहर नदी के तट पर स्थित है जो कई वर्षों से अपना मार्ग बदल रही है और धुलियान के तरफ किनारों को नष्ट कर रही है। 1949 में बह्त अधिक कटाव हुआ था और नदी शहर से 1) से 2 गज (फर्लोंग) के करीब आ गई थी और तट के पास स्थित कुछ गोदाम बह गए थे। यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि 2 जून 1950 के बीच जब बीमा का प्रस्ताव किया गया था और 13/15 अगस्त जब मकान बह गए थे, बीमाकृत मकानों के संबंध में नदी की स्थिति क्या थी, 18 जून, 1950 के विशेष संदर्भ में, जब एक पी.के. घोष (डीडब्ल्यू 2) ने कंपनी की ओर से स्थानीय पूछताछ करने के लिए धुलियान का दौरा किया और 6 जुलाई को जब कंपनी ने जोखिम रद्द कर दिया और पॉलिसी का कवर वापस ले लिया। साक्ष्य दोनों पक्षों से आती हैं लेकिन ज्यादातर सुसंगत होती हैं। बीमित के लिये लालचन्द जैन ने कहा कि 2 जून को घर नदी के किनारे से 400/450 फिट दूर थे (क्यू 73) और उस तारीख को कोई कटाव नहीं हुआ था क्योंकि नदी काफी शांत थी (क्यू.132)। यह जून के दूसरे सप्ताह तक जारी रहा (क्यू. 136)। जून के तीसरे सप्ताह में नदी में उफान शुरू हो गया लेकिन कटाव नहीं हुआ (क्यू.137)। कटाव जून के अंत तक शुरू हो गया (क्यू.142) और तब धारा तेज हो गई (क्यू 144) और दांहिना किनारा बह जाना शुरू हो गया। किनारे के 10-50 फीट के भीतर के घर पहली बार जून के अंतिम सप्ताह में प्रभावित हुए थे (क्यू.180)। उस समय बीमित घर 400/450 फीट की दूरी पर थे। 15 जुलाई 1950 को भी इन घरों और नदी के बीच की दूरी 250

फीट थी (क्यू.179)। सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्जी (पी.इ.2), ओवरसियर और इंस्पेक्टर, धुलिया नगर पालिका ने कहा कि कटाव रथजात्रा के चार या पांच दिन बाद शुरू हुआ जो 20 जून 1950 को या उसके आसपास हुआ था। बिजॉय कुमार (पी.इ.४) सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता एक महत्वपूर्ण गवाह हैं। उन्होंने तीन रिपोर्ट पूर्व प्रस्तुत की। प्रदर्श एफ, जी व एच 27 मई 1949 और 11 सितंबर 1950 को सरकार को भेजा। इन रिपोर्टी में उन्होंने 5 अगस्त 1950 को धुलियान शहर में कटाव होने का विवरण दिया है। उन्होंने जुलाई के पहले सप्ताह में मामलों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जो उन्होंने निःसन्देह कहा होता यदि कटाव पहले ही शुरू हो गया होता। 11 सितम्बर 1950 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के साथ, उन्होंने 9 अगस्त का एक पत्र भेजा जिसमें कहा कि उन्होंनें 5 अगस्त 1950 को धुलियान बाजार का दौरा किया था और पाया कि पुलिस स्टेशन परिसर का कटाव गंगा और बागमारी नदियों के संगम पर एक पखवाड़े पहले ही श्रू हो गया था और यह कटाव प्रतिदिन 20-25 फिट की दर से हुआ होगा। इस साक्ष्य से 6 जुलाई 1950 को या उसके आसपास नदी की स्थिति के बारे में एक राय बनाना संभव है। उस पर हम बाद में आएंगें।

विचारण के समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि पॉलिसी की शर्त 10 पॉलिसी द्वारा कवर किए गए सभी जोखिमों पर लागू होती है, न कि केवल आग से लगने वाले जोखिम पर। यद्यपि पॉलिसी तैयार नहीं थी, प्रस्ताव को कवर नोट की अवधि के दौरान अस्वीकार नहीं किया गया था, विद्वान न्यायाधीश ने कहा, पॉलिसी जारी करने के लिए बाध्य थी और इस प्रकार सुरक्षा की सीमा कम्पनी की सामान्य शर्तों के अनुसार एवं पॉलिसी की शर्तों पर आधारित होगी। इसलिए, सन फायर ऑफिस बनाम हार्ट वगैरह, में न्यायिक समिति के आदेश पर भरोसा करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने शर्त 10 का व्यापक अर्थ दिया और माना कि कंपनी जब चाहे पॉलिसी रद्द करने के अपने अधिकार में थी। विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि यह शर्त अग्नि बीमा की पॉलिसी में एक सामान्य प्रावधान थी और उस शर्त के तहत पॉलिसी को रद्द करने वाले बीमाकर्ता को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और हर बचाव उसके लिए खुला था और कारण, यदि दिया गया हो तो अदालत में उसकी जांच नहीं की जा सकती। अंत में, यह तथ्य कि कोई कारण नहीं दिया गया था या घोष की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी या घोष ने प्रबंधक डंगाली का समर्थन नहीं किया था, को सारहीन माना गया क्योंकि उद्देश्यों जैसे कारणों को सारहीन माना गया था। तद्गुसार मुकदमे को सव्यय खारिज कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के तहत एक अपील दायर की गई थी।

अपील पर पीबी मुखर्जी और एस के दत्ता जे.जे. ने सुनवाई की। अपील पर फैसला मुखर्जी जे. द्वारा दिया गया था। पॉलिसी को रद्द करने से निपटने में विद्वान न्यायाधीश ने शर्त 10 के साथ और बिना उसके मामले पर विचार किया। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर विचार किया कि क्या पॉलिसी की शर्त 10 लागू होती है। विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा न करने के आठ कारण बताये। उन कारणों पर हम अभी आएंगे। विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष यह था कि पॉलिसी अस्तित्व में नहीं आई थी और बीमा के इस अन्बंध को नियंत्रित नहीं करती थी। चूंकि कवर नोट केवल एक महीने के लिए था और इसकी शर्तों पर इसका प्रभाव समाप्त हो गया थाए स्वीकृति पत्र से एक वर्ष के लिए पूर्ण बीमा अनुबंध का उल्लेख किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि यह 3 जुलाई, 1950 (कवर नोट की समाप्ति की तारीख) और 6 जुलाई, 1950 (जब पॉलिसी रद्द कर दी गई थी) के बीच पक्षकारान् के संबंधों को नियंत्रित करेगा और 13/15 अगस्त 1950 तक जब घर बह गए थे। इस प्रकार शर्त 10 को लागू नहीं माना गया। हालांकि यह मानते ह्ए कि ऐसा ह्आ था, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यह अनुचित था और रद्दीकरण तब किया गया जब नुकसान पहले ही शुरू हो चुका था या करीब इतना हो गया था कि कहा जा सकता था कि यह लगभग शुरू हो गया था, कंपनी को इसे लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायिक समिति के निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया और शर्त की चैाड़ाई कम कर दी गई

परिणामस्वरूप मुकदमे व अपील में बीमित व्यक्ति का दावा रूपये 1,10,000 सव्यय डिक्री किया गया।

तथ्य का एक प्रारंभिक प्रश्न है जिस पर नीचे की अदालतों ने स्वयं विचार किया है। बात यह है कि क्या कवर नोट प्रस्तावों की स्वीकृति के पत्र के साथ थे। विद्वान एकल न्यायाधीश का मानना है कि उन्होंने ऐसा किया और डिवीजन बेंच का मानना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे इस बात पर मतभेद पैदा हो गया है कि क्या अग्नि पॉलिसी की शर्त 10 जो दोनों पक्षों की इच्छानुसार नीति का निर्धारण करने में सक्षम बनाती हैए बिल्कुल संचालित है। यह निष्कर्ष किस प्रकार शर्त 10 की उपयुक्तता पर चर्चा की ओर ले जाता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है और अब हम वह करने का प्रयास करेंगे, जो हमने अभी तक नहीं किया है अर्थात् उच्च न्यायालय के दो निर्णयों में दिए गए कारणों का विश्लेषण करेंगें।

स्वीकृति पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक मामले में "रिलेटिव कवर" संलग्न किया गया था। ये पत्र 3 जून 1950 के थे और कहा गया था कि बीमित व्यक्ति का जोखिम 3 जून, 1950 से 3 जून 1951 तक कवर किया गया था और पत्रों के पीछे का पृष्ठांकन हमारे द्वारा पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। उस पृष्ठांकन में कोई नियम नहीं बताया गया था और इसमें किसी पॉलिसी के नियम या शर्तों का उल्लेख नहीं था। कवर नोट्स,

जिनमें से एक को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत भी किया गया है, में बीमाकृत सम्पित को केवल 30 दिनांक की अविध के लिए रखा गया है "आवेदक के प्रस्ताव की शतों और सोसायटी की पॉलिसियों की सामान्य शतों के अधीन"। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि स्वीकृति पत्र में कवर नोट्स के नियमों और संहिताओं और उनके माध्यम से पॉलिसी के नियमों और शतों को शामिल और आकर्षित किया गया है और आगे कहा गया है कि शतों के तहत 30 दिनों के भीतर संबंध को अस्वीकार किया जा सकता है। कवर नोट लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो संबंध बीमा की पूरी अविध के लिए पॉलिसी के नियमों और शतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि कवर नोट स्वीकृति पत्र के साथ होना चाहिए और इस तरह शर्त 10 को अपनी भूमिका निभाने की अनुमित दी गई।

डिविजनल बेंच ने मामले पर अलग नजरिया अपनाया। विद्वान न्यायाधीशों ने नोट किया कि स्वीकृति पत्रों में पूरे वर्ष के लिए जोखिम की बात कही गई थी और कहा गया था कि " " बताया गया कि कवर नोट पर 5 जून की तारीख अंकित थी और उसे प्रस्तावों की स्वीकृति की तारीख 3 जून के बाद भेजा गया होगा। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि "रिलेटिव कवर" को पूरे वर्ष के लिए कवर होना चाहिए था और यदि यह केवल एक महीने के लिए था तो यह "रिलेटिव

कवर" नहीं हो सकता क्योंकि स्वीकृति पत्र में पूरे वर्ष के लिए जोखिम उठाया गया था। इसके बाद उन्होंने माना कि चूंकि कवर नोट स्वीकृति पत्र के साथ नहीं थे इसके बाद उन्होंने माना कि चूंकि कवर नोट स्वीकृति पत्र के साथ नहीं थेए इसलिए बीमित व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि किसी भी पॉलिसी के नियम और शर्तें अनुबंध को नियंत्रित करेंगी। उन्होंने सोसायटी की नीतियों की सामान्य स्थितियाँ वाक्यांश में 'नीति शब्द में गलती पाई क्योंकि यह शब्द नीतियों की अधिकता को दर्शाता है न कि किसी मानक नीति को। उन्होंने टिप्पणी की कि मानक अग्नि पॉलिसी ने शर्त 10 को आग के जोखिम पर लागू किया है न कि बाढ़, चक्रवात आदि के जोखिम पर। उन्होंने पाया कि उक्त संपत्तियों और इसके तहत आग से क्षति के लिए बीमाकृतश अभिव्यक्ति अन्य जोखिमों को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैए हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कवर नोट्स में बाढ़ए चक्रवात आदि से नुकसान या क्षति की बात कही गई थी। आगे बताया गया है कि कवर नोट के शब्द 'पॉलिसी की सभी शर्तें नहीं थे बल्कि केवल 'सामान्य शर्तें थीं और बीमा के कानून पर पुस्तकों का हवाला देकर उन्होंने उस शर्त 10 का निष्कर्ष निकाला जो किसी भी पक्ष को अधिकार देता है अपनी इच्छान्सार पॉलिसी समाप्त करना सामान्य स्थिति नहीं मानी जा सकती । उन्होंने देखा कि यह ऐसी शर्त नहीं थी जो आमतौर पर अंग्रेजी नीतियों में शामिल होती थी और औपनिवेशिक व

अविकसित देशों में प्रचलन में थी। उनका मानना था कि यदि अग्नि पॉलिसी को बाढ़ आदि के जोखिम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था तो नए जोखिमों को स्पष्ट रूप से शर्त 10 के अधीन बनाया जाना चाहिए थाए जैसे अग्नि जोखिम को इसके अधीन बनाया गया था और यह कि केवल अन्य जोखिमों को कवर करने के लिए अग्नि पॉलिसी का विस्तार करके प्रत्येक अलग.अलग खंड में संशोधन और व्याख्या करने का आश्वासन दिया गया था। शर्त 10 को अनुचित मानते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी 6 जुलाई को पॉलिसी रद्द नहीं कर सकती क्योंकि तब तक कोई पॉलिसी अस्तित्व में नहीं थी और कवर नोट जो पॉलिसी को संदर्भित करता था वह स्वतः काम कर चुका था। अंततः उनका मानना है कि रद्दीकरण, किसी भी स्थिति में, जोखिम शुरू होने के बाद किया गया था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था। इन कारणों से दावा डिक्री कर दिया गया। ट्रायल जज ने पाया कि हर्जाने की राशि तय करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था लेकिन डिवीजनल बेंच ने मामले पर पुनर्विचार किया और अपना निष्कर्ष दिया।

हालाँकि डिविजनल बेंच ने विस्तृत चर्चा की (जिनमें से कुछ शायद पूरी तरह से आवश्यक नहीं थीं) इस मामले में दायित्व की समस्या को पक्षकारान् के लिए उपस्थित वकील द्वारा अच्छी तरह से जांच की गई थी। उन्होंने तीन अलग-अलग शीर्षकों के तहत मामले पर बहस की, जो है:

- (ए) क्या शर्त 10 तथ्यों पर लागू हुई थी,
- (बी) यदि ऐसा हुआ, तो इसका अर्थ कैसे लगाया जाए, और
- (सी) क्या पॉलिसी रद्द करना कानूनन वैध था हम इन तीन व्यापक शीर्षकों के तहत मामले पर विचार करते हैं।

शर्त 10 का लागू होना इस बात पर निर्भर करता है कि पक्षकारान् के बीच बीमा के इस अनुबंध में पॉलिसी की शर्तों को किस हद तक शामिल किया जा सकता है। कवर नोट्स से संबंधित एक बिंदु को छोड़कर अनुबंध के गठन से संबंधित तथ्य स्पष्ट हैं और हमारी राय में डिवीजनल बेंच द्वारा इसे अनुचित प्रमुखता दी गई है। इससे कोई आवश्यक फर्क नहीं पड़ता कि कवर नोट्स स्वीकृति पत्रों के साथ थे या दो दिन बाद भेजे गए थे। यह संभव है कि स्वीकृति पत्र स्वयं 5 जून को भेजे गए हों। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही समय में दिए गए दो पत्रों पर अलग-अलग तारीखें लिखी होती हैं। स्वीकृति पत्रों में 'रिलेटिव कवर' का उल्लेख है लेकिन'

उपयोग अनावश्यक कानूनता का एक उदाहरण है और इससे संचार का यह आशय नहीं जुड़ता कि एक कवर नोट भेजा जा रहा था। यह स्पष्ट है कि यदि उस अविध में जिसके दौरान कवर नोट प्रभावशील था बीमा करने से इंकार कर दिया गया था तो बीमित व्यक्ति पॉलिसी की मांग नहीं कर सकता था या इस बात पर जोर दे सकता था कि पॉलिसी के बिना

बीमा था मानक या अन्यथा और किसी भी शर्त के अधीन नहीं था स्वीकृति के कारण स्वीकृति पत्रों में उनके संदर्भ के प्रभाव को ख़राब किए बिना कवर नोट बाद में भेजे जा सकते थे। कवर नोट संलग्न करने की आकस्मिक चुक के कारण बीमित व्यक्ति को स्वीकृति पत्र के तहत कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिला। संपत्ति का बीमा कोई दांव नहीं बल्कि एक जाना-माना व्यावसायिक सौदा है। कवर नोट्स के साथ पढ़े गए प्रस्ताव की स्वीकृति से बीमित व्यक्ति को उसके द्वारा खरीदे गए बीमा के संबंध में पॉलिसी की मांग करने का अधिकार मिल जाता है और वह केवल पॉलिसी में निर्धारित तरीके से जोखिम के विरूद्ध कवर होने का दावा कर सकता है। इस परिणाम से बचने के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने बीमित व्यक्ति की ओर से बहस करते हुए सुझाव दिया कि स्वीकृति पत्र के पीछे का पृष्ठांकन कवर नोट था और इसमें किसी पॉलिसी का उल्लेख नहीं था। यह स्थिति स्पष्टतः अस्थिर थी। कवर नोटस प्रस्तावों की स्वीकृति का एक अभिन्न अंग थे और दोनों को एक साथ पढा जाना था।

बीमा का अनुबंध वाणिज्यिक लेनदेन का एक प्रकार है जिसमें एक उचित प्रस्ताव के पूरा होने से पहले या जब प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो या पॉलिसी डिलीवरी के लिए तैयारी में हो तब भी कवर नोट भेजने की एक अच्छी तरह से स्थापित व्यावसायिक प्रथा है। कवर नोट एक अस्थाई और सीमित समझौता है। यह स्वतः निहित हो सकता है या इसमें

भविष्य की पॉलिसी के संदर्भ में नियम और शर्ते शामिल हो सकती है। जब कवर नोट इस तरीके से पॉलिसी को शामिल करता है तो इसमें नियम और शर्तों को दोहराना नहीं होता है बल्कि केवल एक विशेष मानक पॉलिसी का उल्लेख करना होता है। यदि प्रस्ताव एक मानक पॉलिसी के लिए है और कवर नोट इसका उल्लेख करता है तो यह माना जाता है कि बीमित व्यक्ति ने उस पॉलिसी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। पॉलिसी और उसके नियमों और शर्तों का संदर्भ प्रस्ताव या कवर नोट या यहां तक कि कवर नोट सहित स्वीकृति पत्र में भी व्यक्त किया जा सकता है। पॉलिसी के नियमों और शर्तों का समावेश पक्षकारान के बीच पारित होने वाले दो या दो से अधिक दस्तावेजों में संदर्भों के संयोजन से भी उत्पन्न हो सकता है। प्रस्ताव, कवर नोट और पॉलिसी जैसे दस्तावेज़ व्यावसायिक दस्तावेज़ हैं और उनकी व्याख्या करने के लिए व्यावसायिक व्यवहार और अभ्यास को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कवर नोट के संचालन के दौरान, पक्षकारान् के संबंध इसके नियमों और शर्तों, यदि कोई हों, द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन आमतौर पर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार सौदेबाजी की जाती है और जारी की जाती है। जब ऐसा होता है तो पॉलिसी की शर्तें आरंभिक होती हैं लेकिन अस्थाई कवर की अवधि के बाद, संबंध केवल पॉलिसी के नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं जब तक कि इस बीच बीमा अस्वीकार नहीं किया जाता है। पॉलिसी

जारी करने में देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंध तब भी भविष्य की नीति द्वारा शासित होते हैं यदि कवर नोट्स पर्याप्त संकेत देते हैं कि ऐसा होगा । अन्य मामलों में बीमा के अनुबंध और किसी भी अन्य अनुबंध के बीच कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि बीमा के अनुबंध में अत्यन्त अच्छे विश्वास की आवश्यकता होती है अर्थात् बीमाधारक की ओर से अच्छा विश्वास और अन्बंध को प्रस्तावितकर्ता के विरुद्ध माना जाने की संभावना है जो कि अस्पष्टता या संदेह की स्थिति में कंपनी के विरूद्ध है। प्रस्ताव की अयोग्य स्वीकृति होने पर एक अनुबंध बनता है। स्वीकृति लिखित रूप में व्यक्त की जा सकती है या यदि बीमाकर्ता प्रीमियम स्वीकार करता है और उसे बरकरार रखता है तो इसे निहित भी किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति के मामले में उसके जिम्मे एक सकारात्मक कार्य जिसके द्वारा वह पॉलिसी को पहचानता या लागू करना चाहता है इसकी पृष्टि के समान है। इस स्थिति को स्वयं बीमित व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से पहचाना था क्योंकि उसने लिखा था, कवर नोट के समय की समाप्ति पर बंद करें या तो उस अवधि के समाप्त होने से पहले उसे एक पॉलिसी जारी की जानी चाहिए या कवर नोट को समय में बढ़ाया जाना चाहिए। बीमा के अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करते समय न्यायालय का कर्तव्य उन शब्दों की व्याख्या करना है जिनमें अनुबंध पक्षकारान् द्वारा व्यक्त किया गया है क्योंकि यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह एक नया अनुबंध करे, चाहे

वह कितना भी उचित क्यों न हो, यदि पक्षकारान् ने स्वयं ऐसा नहीं किया है। प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र और कवर नोट्स को देखने से यह स्पष्ट है कि मानक पॉलिसी के तहत बीमा का अनुबंध आग के लिए था और बाढ़, चक्रवात आदि को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था।

स्वीकृति पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया थ कि कवर नोट भेजे जा रहे थे। बीमा का अनुबंध कवर नोट्स द्वारा कवर की गई अवधि के लिए कवर नोट्स पर आधारित था। जिन 30 दिनों के दौरान कवर नोट संचालित हए, उनमें कुछ भी नहीं हुआ। यह सच है कि स्वीकृति पत्र से पता चलता है कि जोखिम पूरे वर्ष के लिए कवर किया गया था, न की 30 दिनों के लिए। यह व्यक्त करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था कि प्रस्ताव की स्वीकृति पहली बार में केवल 30 दिनों के लिए लागू होगी, जिसके दौरान कंपनी पॉलिसी को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। बीमा के अनुबंध के चार आवश्यक तत्व है, (1) जोखिम की परिभाषा, (2) जोखिम की अवधि, (3) प्रीमियम और (4) बीमा की राशि। बीमा कानून पर मैकगिलिवे्र (5 वां संस्करण) खंड 1, पैराग्राफ 656, पृष्ठ 316 देखें। लेकिन जो पॉलिसी जारी की जाती है उसमें इन आवश्यक बातों से कई अधिक शामिल है क्योंकि यह पक्षकारान के अधिकारों को निर्धारित और मापता है और प्रत्येक पक्ष के कुछ दायित्व हैं जिन्हें भी परिभाषित भी किया गया है। पॉलिसी में आग के खिलाफ संपत्ति का बीमा करना उददेश्य नहीं है,

बल्कि संपत्ति के मालिक को हए नुकसान के खिलाफ बीमा करना है। पॉलिसी न केवल जोखिम और उसकी अवधि को परिभाषित करती है, बल्कि विशेष नियम और शर्तें भी निर्धारित करती है जिसके तहत पॉलिसी किसी भी पक्ष पर लागू हो सकती है। भले ही स्वीकृति पत्र अवधि के मामले में कवर नोट्स से परे चला गया हो, प्रस्तावित पॉलिसी के नियम और शर्त मामले को नियंत्रित करेंगी क्योंकि संपत्ति का बीमा करने का अनुबंध पूरा हो जाता है, तो यह महत्वहीन है कि क्या पॉलिसी वास्तव में न्कसान के बाद वितरित की जाती है और इसी कारण से पॉलिसी की स्वीकृति और वितरण के बीच पक्षकारान के आधिकार पॉलिसी द्वारा नियंत्रित होती है। भले ही कोई शर्तें निर्दिष्ट न हों, ऐसे मामलों में प्रथागत रूप से जारी की गई पॉलिसी में निहित शर्ते लागू होंगी। प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (खंड 44, पृष्ठ 953) में निम्नलिखित है:

"जहां अग्नि बीमा की पॉलिसी का बीमा करने या जारी करने का अनुबंध पॉलिसी के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट नहीं करता है, यह एक सामान्य नियम है कि यह माना जाएगा कि पक्षकारान ने ऐसी शर्तें और सीमाएं वाली नीति के एक रूप पर विचार किया है जो ऐसे मामलों में आमतौर पर है।"

रिचर्डस ऑन इंश्योरेंस (5 वां संस्करण) पर खंड 3, पृष्ठ 1296, पैराग्राफ 390 भी देखें। ईम्स बनाम होम इंश्योरेंस (1) संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय में देखें।

"यदि कोई भी प्रारंभिक अनुबंध तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसमे जारी की जाने वाली पॉलिसी में शामिल शर्तों को सूक्ष्मता से निर्दिष्ट न किया जाए, तो ऐसा कोई भी अनुबंध कभी नहीं किया जा सकता या कभी भी किसी काम का नहीं होगा। ऐसे अनुबंध को बनाए रखने का मूल कारण यह है कि पक्षकारान का उस प्रारंभिक अवधि के दौरान उनका लाभ मिल सकता है जब कागजात को सही किया जा रहा है और प्रेषित किया जा रहा है। यह पर्याप्त है कि यदि एक पक्ष बीमा कराने का प्रस्ताव करता है, और दूसरा पक्ष बीमा करने के लिए सहमत होता है, और विषय, अवधि, राशि और बीमा की दर सुनिश्चित या समझी जाती है, और प्रीमियम मांगे जाने पर भुगतान किया जाता है। यह माना जाएगा कि उन्होंने पॉलिसी के ऐसे रूप पर विचार किया है, जिसमें ऐसी शर्ते और सीमाएं निहित है जो ऐसे मामलों में सामान्य हैं, या पक्षकारान के बीच

पहले इस्तेमाल की गई है। यह बात का अर्थ और कारण है, और किसी भी विपरीत आवश्यकता को इससे प्रभावित होने वाले पक्ष को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

जनरल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कारपोरेशन बनाम क्रोनक (2) में, यह भी फैसला सुनाया गया था कि प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को कंपनी द्वारा जारी की गई पॉलिसी के सामान्य प्रकार के लिए आवेदन किया हुआ माना जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब कोई पूर्व शर्तें हो कि पॉलिसी तब वितरित की जानी चाहिए जब आश्वासन देने वाला जोखिम में न हो अन्यथा वह जोखिम में है। मैकगिलिव्रे (खंड 1, पृष्ठ 325, पैराग्राफ 675) देखें। ऐसे मामले में स्वीकृति केवल एक सूचना है कि आश्वासन देने वाला एक पॉलिसी जारी करने को तैयार है लेकिन कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं होगा (उक्त पैराग्राफ 679, पृष्ठ 328)। वर्तमान मामले में, ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं थी और कंपनी पूरे समय जोखिम में थी। चूंकि कंपनी की पॉलिसी पर बीमा मांगा गया था, इसलिए सामान्य पॉलिसी जारी की गई होगी और चूंकि बीमा 3 जून, 1950 से था, इसलिए पॉलिसी उसी तारीख से संबंधित होगी। पॉलिसी का बीमा अनबंध में नहीं जुड़ता है। अनुबंध के प्रारम्भिक नियम और शर्ते बाद में पॉलिसी में विलीन हो जाती है और फिर नियम और शर्तें स्पष्ट हो जाती है।

इसलिए इस मामले में आश्वासन देने वाले का प्रयास यह स्थापित करने का रहा है कि कवर नोट्स की सीमा समाप्त होने के कारण, पक्षकारान पर कोई बंधन नहीं है और पॉलिसी का संदर्भ कवर नोट्स में है, न कि स्वीकृति पत्र, पॉलिसी के नियम एवं शर्तें में लागू नहीं थी। हम संतुष्ट है कि यह सही स्थिति नहीं हैं। स्वीकृति पत्रों में स्पष्ट रूप से कवर नोट्स का उल्लेख किया गया है और कवर नोट्स में स्पष्ट रूप से पॉलिसी का उल्लेख किया है। इसलिए, 30 दिनों की अवधि के दौरान जब कवर नोट संचालित होते थे उसके बाद भी, पॉलिसी के नियम और शर्ते पक्षकारान के बीच संबंधों को नियंत्रित करती थी। हम पहले ही मान चुके है कि चूंकि केवल एक मानक अग्नि पॉलिसी थी, बह्वचन शब्द का उपयोग "नीतियों से कोई फर्क नहीं पड़ा और कवर नोट भेजने में देरी, यदि कोई हो, भी महत्वहीन थी। सामान्य पॉलिसी की नियम और शर्त तदनुसार पक्षकारान के संबंधों को नियंत्रित करती है और शर्त 10 लागू करती है।

हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि पॉलिसी स्वयं कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि इसे जारी होने से पहले ही रद्द कर दिया गया था और पॉलिसी के निर्माण के साथ रद्दीकरण का समर्थन पर ध्यान दिया गया और शामिल किया गया। यह तर्क दिया गया कि शर्त 10 बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी स्वंय लागू होने से पहले ही रद्द हो गई थी। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि शर्त 10 पक्षकारान के बीच तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता और आश्वासन प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं किया जाता और चूंकि ऐसी कभी नहीं हुआ, इसलिए रद्दीकरण अनुचित था। यह तर्क शायद ही खुला है, क्योंकि बीमाकर्ता स्पष्ट रूप से अपने वाद को पॉलिसी पर आधारित कर रहा है। अपनी याचिका में उन्होंनें इस पॉलिसी का हवाला किया। बीमाकर्ता पॉलिसी पर आधारित होने के अलावा मुकदमें को बरकरार नहीं रख सकता है, क्योंकि जब तक कोई पॉलिसी और उन शर्ती को नहीं पढ़ता, जिन पर यह प्रभावी थी, केवल प्रस्तावों और स्वीकृति पत्रों को पढ़ने से कोई शर्तें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जब संपत्ति का बीमा करने का अनुबंध पूरा हो जाता है, तो यह मायने नहीं रखता कि पॉलिसी वितरित की गई है या नहीं, क्योंकि पक्षकारान के अधिकारों के लिए पॉलिसी द्वारा विनियमित किया जाता है जिन्हें वितरित किया जाना चाहिए। इस तरह मानक अग्नि-पॉलिसी के नियम और शर्तें भी पॉलिसी जारी न होने पर भी लागू होगी

आगे यह तर्क दिया गया कि अभिव्यक्ति "सोसाईटी की पॉलिसी की सामान्य शर्तें को शर्त 10 को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, जो एक सामान्य शर्त नहीं थी जहां यह कंपनी को अपनी इच्छानुसार पॉलिसी को समाप्त करने का अधिकार देती है। यह सही नहीं है। ऐसी स्थिति का उल्लेख बीमा के कानून की लगभग सभी पुस्तकों में किया गया है। इंग्लैंडके हेल्सबरी नियम (तीसरा संस्करण) खंड 22, पृष्ठ 245, पैराग्राफ 474, बीमा कानून पर मैकगिलिवेर (पांचवा संस्करण) खंड 2, पृष्ठ 963, पैराग्राफ 1981, वेलफोर्ड और ओटर-बैरी का अग्नि बीमा (चौथा संस्करण), पृष्ठ 178, 179 और रिचर्ड्स ऑन इंश्योरेंस (पांचवा संस्करण) खंड 3, पृष्ठ 1759, पैराग्राफ 531 देखें। द सन फायर ऑफिस बनाम हार्ट एंड अदर्स (1) में ऐसी एक शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि चर्चा भी की गई है। द सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लि. बनाम हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी लि. (1) में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के एक फैसले में ऐसी शर्त को शामिल करने में कुछ भी असामान्य नहीं था और इसलिए सामान्य शर्तों के संदर्भ में शर्त 10 का संदर्भ शामिल होगा।

यह शर्त पक्षकारान् को किसी भी समय पॉलिसी रदद करने का आपसी अधिकार देती है। यह बीमाकर्ता को अपनी इच्छानुसार पॉलिसी को रदद करने का अधिकार देता है। यह तर्क दिया गया कि ऐसी शर्त इतनी अनुचित थी कि इसे टिके रहने की अनुमित नहीं दी जा सकती। यह तर्क दिया गया था कि एसएसई हाई टोंग बैंक लिमिटेड बनाम रैम्बलर साइकिल कंपनी लि. के अधिकार पर शर्त की अत्यधिक चैड़ाई को एक निहित सीमा द्वारा कम किया जाना चाहिए जो यह थी कि अनुबंध के मुख्य उद्देश्य और इरादे को विफल नहीं होने दिया जाना चाहिए और वह आपित और इरादा बाढ़ के खिलाफ संपित का बीमा करना था और बाढ़ शुरू होने पर पॉलिसी

रदद करना अनुबंध की मुख्य आपित और इरादे को विफल कर देगा। यह तर्क दो स्थितियों को मिलाता है। यह पहला स्पष्ट सिद्धांत का प्रश्न है। बीमा रद्द करने के लिए ऐसी पारस्परिक शर्त शामिल करने में कुछ भी गलत नहीं है। एक बीमित व्यक्ति ऐसी शर्त लागू करना चाह सकता है जब पॉलिसी उस पॉलिसी से भिन्न पाई जाती है जिसे वह स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था या इसमें कोई नियम या शर्त शामिल थी जिससे वह सहमत नहीं था। वह किसी अन्य कम्पनी से वही पॉलिसी स्वीकार नहीं कर सकता जिसके लिए उसने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। यदि कंपनी अपनी सम्पत्ति और व्यवसाय दूसरे को हस्तांतरित करती है तो वह इस शर्त को लागू कर सकता है। जिस प्रकार बीमाधारक बिना कोई कारण बताए और अपनी इच्छा से पॉलिसी समाप्त करना चाह सकता है, उसी प्रकार बीमाकर्ता भी ऐसा कर सकता है।

सन फायर कार्यालय बनाम हार्ट में प्रिवी काउंसिल द्वारा इस तरह के खंड पर विचार किया गया था। यह उसके खिलाफ बीमा पॉलिसी का मामला था। गन्ने के कुछ खेतों का आग से बचाव के लिए बीमा किया गया था। बीमे के बाद तीन बार आग लगी और एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ कि आग और लगेगी। पॉलिसी में एक शर्त थी कि बीमाकर्ता 'ऐसे परिवर्तन के कारण, या किसी अन्य कारण से' नोटिस द्वारा पॉलिसी को

समाप्त कर सकते हैं और बीमाकर्ताओं ने इस शर्त के तहत पॉलिसी रद्द कर दी। ऐसी स्थिति के बारे में लार्ड वाटसन ने कहा था कि-

"....... बीमाकर्ताओं को अपनी मुद्रा के दौरान अपने अनुबंध से खुद को मुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए, इसे नोटिस के समय तक पूरी ताकत से छोड़ दें जिन शब्दों में दृढ़ संकल्प की शिक्त व्यक्त की जाती है, वे स्वयं द्वारा लिए गए हैं, वे बहुत विस्तृत और व्यापक है। अपने प्राथमिक और स्वाभाविक अर्थ के अनुसार, वे कहते हैं कि, शिक्त के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए, भविष्य के दायित्व से छुटकारा पाने के लिए बीमाकर्ताओं की ओर से इच्छा के अस्तित्व के अलावा कुछ भी आवश्यक नहीं है, चाहे ऐसी इच्छा उन कारणों से प्रेरित हो जो पॉलिसी को संलग्न करने से रोकते हो या किसी अन्य कारण से जो भी हो।"

आगे के प्रश्न से निपटने में कि क्या कोई कारण निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और यदि सौंपा गया है तो क्या वे ऐसे होने चाहिए जो कानून की अदालत को संतुष्ट करने चाहिए, यह आगे देखा गया:

"सवाल यह है कि क्या यह खंड बीमाकर्ताओं को अपने निर्णय पर कार्य करने का अधिकार देता है, या क्या वे बाध्य है, यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीश या जूरी की संत्षि के लिए आरोप लगाने और साबित करने के लिए न केवल यह कि उनकी ओर से इच्छा मौजूद है लेकिन यह कि उनके पास इस पर विचार करने के लिए उचित आधार है। यदि नीति का निर्धारण उसके व्यवसाय के लाभ के लिए होगा, तो यह स्पष्ट रूप से इसे समाप्त करने के इच्छ्क कार्यालय के लिए एक उचित आधार होगा, और यह प्राथमिकता, कोई यह मान सकता है कि बीमाकर्ताओं को स्वयं सबसे अच्छा होना चाहिए, न कि केवल इस बात की सक्षम जांच करना कि उनके व्यवसाय को क्या लाभ होगा। एक बीमा कार्यालय इसे विवेकपूर्ण मान सकता है और अपने बकाया कार्यों को सीमित करने का संकल्प ले सकता है और जब तक कि खण्ड के शब्द स्पष्ट रूप से इसके विपरीत न हों, यह नहीं माना जा सकता है कि पक्षकारान विवेकपूर्ण प्रशासन के ऐसे प्रश्न को कानून की अदालत में जांच का विषय बनाना चाहती थी।"

डिविजनल बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने न्यायिक समिति के निर्णय का पालन नहीं किया क्योंकि उन्हें यह अस्वीकार्य लगा। लेकिन इसी तरह की स्थिति का एक समान दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी मामले में लिया गया था। सरकार जे ने बताया कि इस फॉर्म में एक खंड पॉलिसियों में एक सामान्य शर्त थी और इसलिए इसे उचित माना जाना चाहिए और इच्छानुसार समाप्त करने का अधिकार परिस्थितियों के कारण उचित कारण से समाप्त करने के अधिकार के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है । उस मामले में हार्टफोर्ड कार्यालय ने 20 मार्च 1947 और मार्च 1948 के बीच अमृतसर शहर में आग से कुछ वस्तुओं का बीमा किया था। पॉलिसी को दंगों या नागरिक हंगामे से नुकसान तक बढ़ाया गया था। जुलाई 1947 में पंजाब में हुए दंगों में अमृतसर के बकरवाना बाज़ार में एक गोदाम, जहाँ बीमाकृत सामान रखा हुआ था लूट लिया गया और कुछ सामान खो गया। हार्टफोर्ड कार्यालय को सूचित किया गया और 7 अगस्त 1947 को उन्होंने लिखा कि सामान को सुरक्षित स्थान पर हटा दिया जाए अन्यथा पॉलिसी 10 अगस्त 1947 के बाद शर्त 10 के तहत रद्द कर दी जाएगी जो यहां की शर्त 10 के समान थी। 15 अगस्त 1947 को आग से सामान नष्ट हो गया। हार्टफोर्ड कार्यालय को उक्त शर्त द्वारा संरक्षित माना गया था। नियम का कारण यह प्रतीत होता है कि जहां पक्षकारान कुछ शर्तों पर सहमत होते हैं जो उनके रिश्ते को विनियमित

करने के लिए होती हैं यह अदालत के लिए एक नया अनुबंध बनाने के लिए नहीं है, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न होए अगर पक्षकारान ने इसे अपने लिए नहीं बनाया है। यहां अनुबंध ने पक्षकारान को किसी भी समय पॉलिसी रद्द करने का समान अधिकार दिया और इसलिए बीमित व्यक्ति पॉलिसी रद्द करने की शर्त लागू कर सकते हैं।

यह तर्क दिया गया था; और डिविजनल बेंच ने ऐसा माना है कि यह रद्दीकरण अप्रभावी था क्योंकि जोखिम पहले ही शुरू हो चुका था और कंपनी की देनदारी शुरू होने के बाद पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती थी। एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, यह बिल्कुल सही है। शर्त 10 का उद्देश्य जोखिम को रद्द करना है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसके लिए दायित्व से बचना नहीं है या जोखिम से बचना है जो पहले से ही नुकसान में बदल रहा है। स्पष्ट है कि घर में आग लगने के बाद अग्नि पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि जब तक जोखिम पहले ही शुरू नहीं हो गया है या इतना निकटस्थ नहीं हो गया है कि यह अनिवार्य रूप से घटित होना ही है, तब तक ऐसे खंड को लागू किया जा सकता है। यदि संपत्ति का बाढ़ से बचाव के लिए बीमा कराया गया है तो बीमा कंपनी बाढ़ से पहले पॉलिसी रद्द करने के लिए मोटर साइकिल पर कोरियर भेजने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर यह सोचा जाता है कि कोई विशेष बांध पूरी तरह से स्रक्षित नहीं है तो बीमा कंपनी बांध के

वास्तव में टूटने या ढहने से पहले बाढ़ के खिलाफ पॉलिसी को रद्द करने की हकदार होगी। पॉलिसी के तहत दायित्व शुरू होने या अपरिहार्य होने से पहले रद्दीकरण उचित रूप से संभव है और यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है कि रद्दीकरण वैध है या अवैध।

वर्तमान मामले में यह हमेशा स्पष्ट था कि बरसात के मौसम में गंगा में बाढ़ आ जाए लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह किनारों को इस तरह से नष्ट करना शुरू कर देगी कि ये घर, जो किनारे से 400/500 फीट की दूरी पर थे अपरिहार्य रूप से बह जायेंगे। इस प्रकार सवाल यह है कि क्या पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता के दायित्व शुरू होने के बाद रद्दीकरण किया गया था या नुकसान अपरिहार्य हो गया था। यहां हमें उन साक्ष्यों को देखना चाहिए जिनका सारांश पहले दिया गया था।

हम विशेष रूप से दो तारीखों को लेकर चिंतित हैं और वे हैं 18 जून 1950 जब घोष ने धुलियान का दौरा किया था और 6 जुलाई जब पॉलिसी रद्द कर दी गई थी। लालचंद जैन (पीडब्ल्यू 1) के अनुसार जब प्रस्ताव बनाया गया था तब घर 400/500 फीट दूर थे। जून के दूसरे सप्ताह तक नदी शांत रही। जून के तीसरे सप्ताह में ही इसमें वृद्धि शुरू हुई। इस प्रकार 18 जून कोए जब घोष ने उस स्थान का दौरा किया तो कोई बाढ़ नहीं थी और कोई कटाव नहीं था। घोष की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है लेकिन वह केवल नुकसान की संभावना का अनुमान लगा सकते थे और इससे अधिक

नहीं। जून के तीसरे सप्ताह में भी कटाव नहीं हुआ और जून के अंत तक कटाव शुरू हो गया। 15 जुलाई को भी नदी और घरों के बीच की दूरी 250 फीट थी (देखें क्यू 179)। चूंकि कटाव की दर लगभग 20/25 फीट प्रति दिन थी (बिजॉय कुमार पीडब्लू 4 के अनुसार) 6 जुलाई को भी घर 400/500 फीट दूर थे। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि नुकसान शुरू हो गया था या यह इतना निश्चित हो गया था कि यह अपरिहार्य था या रद्दीकरण अपरिहार्य नुकसान की प्रत्याशा में और ज्ञान के साथ किया गया था। रद्दीकरण ऐसे समय में किया गया था जब कोई भी निश्चितता के साथ नहीं कह सकता था कि घर इतने खतरे में थे कि न्कसान श्रू हो गया था या अपरिहार्य हो गया था इसे स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है इसलिए यह मामला सन फायर ऑफिस और हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी मामलों के नियम के अंतर्गत आता है। इसलिए पॉलिसी की शर्त 10 के तहत बीमित व्यक्ति के पास इसे रद्द करने का अधिकार है। पॉलिसी तैयार न होने के कारण इसे क्रियान्वित करना एवं निरस्त करना उचित था। रद्दीकरण की कानूनी कार्रवाई से वादी का पॉलिसी पर और उसे लागू करने का अधिकार खो गया।

परिणामस्वरूप अपील सफल होनी चाहिए। यह स्वीकार की जाती है। डिविजनल बेंच द्वारा पारित डिक्री को रद्द किया जाता है और मुकदमे को खारिज करने वाले जी.के. मित्तर,जे. के फैसले को बहाल किया जाता है

हालाँकि कॉस्ट को घटना के अनुरूप होना चाहिए, हम सोचते हैं कि इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में हमें कॉस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं देना चाहिए।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।